भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 9

(जिसका उत्तर सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

देश में कॉरपोरेट निवेश में गिरावट

9. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कॉरपोरेट निवेश में हाल ही में आई गिरावट का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है अथवा आरंभ किया है;

(ख): यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है/निवेश के स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार चिह्नित किए गए कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या सरकार ने कॉरपोरेट निवेश को बढ़ाने और कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए कोई विशिष्ट नीतिगत उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है और कॉरपोरेट विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में इनसे क्या परिणाम अपेक्षित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में कॉरपोरेट निवेश और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'देश में कॉरपोरेट निवेश में गिरावट' के संबंध में दिनांक 1 दिसंबर, 2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 9 के उत्तर के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी, नहीं। सरकार ने देश में कॉरपोरेट निवेश में हाल ही में आई गिरावट का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है अथवा आरंभ नहीं किया है।

तथापि, वर्ष 2022-23 में, संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) निजी क्षेत्र से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) संबंधी डेटा प्राप्त करने के लिए एक व्यापक पद्धति विकसित करे। इस सिफारिश का उत्तर देते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश के उद्देश्यों संबंधी पहला भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण किया और निष्कर्ष अप्रैल 2025 में जारी किए गए। इस सर्वेक्षण के परिणाम वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक चार वर्षों की अवधि में कुल पूंजीगत व्यय में 66.3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं[1]।

(ग), (घ) और (ङ): पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने समय-समय पर कारपोरेट निवेश को सुविधाजनक बनाने और व्यावसायिक दृष्टिकोणों को बेहतर करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ, व्यापार में सुगमता, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क, भारत ट्रेड नेट, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति, कराधान नीतिगत सुधार, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया पर जोर देना, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में व्यापार में सुगमता में सुधार के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना (बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान) (बीआरएपी), वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और पीएम गति शक्ति शामिल हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक उपायों से देश भर में कॉरपोरेट निवेश और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिला है।

****

[1] https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/press_note_CAPEX_25042025_Final_29042025.pdf